

Ecological Imbalance: A challenge for Human Race

A seminar was organized on the topic “Ecological Imbalance: A challenge for Human Race” on 28th Sep. 2016 in the Multipurpose Hall.

Many of the distinguished scholars came and participated in the deliberations as resource persons and delegates. Dr. A.S. Ahluwalia, Head Dept. of Life Sciences, Panjab University, Chandigarh presented a thought provoking key note address, which set the tone of the entire seminar. Dr. Bhiswaroop Mukherjee, Prof. of Botany, Ranchi University, Ranchi and distinguished scholar was another expert transcend a resource Person on environmental issues. He presided over the 1st academic session. Sri Dinesh Kumar Mishra a celebrated columnist and a noted environmentalist was another distinguished resource person, who enlightened the audience with an inspiring presentation.

There was participation from all the local colleges and many teachers from the Vinoba Bhave University, Hazaribag.

The organising secretary of the seminar was **Dr. Ranjana Das, Co-ordinator, IQAC.**

















Press Release

जीएन कॉलेज. 'पर्यावरणीय असंतुलन : मानव जाति के लिए एक चुनौती' पर बोले डॉ अहलूवालिया

पर्यावरण चिंता के बिना विकास घातक

जीएन कॉलेज में 'पर्यावरणीय असंतुलन : मानव जाति के लिए एक चुनौती' विषयक संगोष्ठी पर बोले हुए वक्ताओं ने आदमखोर विकास के संदर्भ में पर्यावरण की चिंता की अहमियत पर प्रकाश डाला. बताया कि पर्यावरण की चिंता से कट कर किया गया विकास अंततः मनुष्यविरोधी हो जाता है.

वर्तव्य संवाददाता > धनबाद

यूजिसी के सौजन्य से आयोजित संगोष्ठी के मुख्य वक्ता पंजाब यूनिवर्सिटी के वनस्पति विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. एएस अहलूवालिया ने कहा कि मौजूदा दौर में विकास से अधिक जरूरी यह हो गया है कि विकास के कारण प्रभावित होने वाले पर्यावरणीय असंतुलन पर कैसे कवायु पाया जावे. यह दिन दूर



संगोष्ठी में सासद पीएन सिंह ने कहा कि विकास व परिकल्पना का तफाजा है. विकास मानवता के लिए खतरा न बने, इसके प्रति भी सजगता केहद जरूरी है. मौके पर विचारक राज सिन्हा ने कहा कि पर्यावरणीय असंतुलन के दुष्प्रभाव लगातार सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके हम इसके संरक्षण के प्रति सजग नहीं हो रहे हैं.

नहीं जब जल व वायु स्रोत के अभाव का मानव जीवन पर दुष्परिणाम सामने आयेगा.
पर्यावरणीय चिंता से रुबरू : डॉ अहलूवालिया ने बताया कि प्रकृतिक स्रोतों का जैसा दुरुपयोग हो रहा है, लगता है कि भावी पीढ़ी को देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. उन्होंने प्राकृतिक संपदा व स्रोतों के साथ खिलवाड़ रोकने

के उपाय भी बताये. इसके लिए सरकार के साथ-साथ आमजन को सहभागिता पर बल देना.
इनकी थी सहभागिता : मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष आरएस चहल व सचिव दिलजीत सिंह ग्रेवाल ने भी अपने विचार रखे. प्राचार्य प्रो. पी शेखर ने स्वागत भाषण दिया. विभागाध्यक्ष (इतिहास) प्रो रंजना दास

सेमिनार की को-ऑर्डिनेटर थीं. मंच संचालन प्रो. पुष्प तिवारी ने किया. पीके राव कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एसके अग्रवाल, एसएसएलएनटी महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एसकेएल दास, कतरस कॉलेज के प्राचार्य पीके झा, आरएस मोर कॉलेज की प्राचार्य डॉ. किरण सिंह सहित विभिन्न कॉलेजों के प्रतिनिधि.

विवि शिक्षकों की दूसरी किस्त निर्गम का आदेश

धनबाद. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत झारखंड के विद्यार्थी शिक्षकों को देय राशि का दूसरा किस्त जारी कर दिया है. यह जानकारी पूर्व मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री प्रो. रीता वर्मा ने दी है. उन्होंने इसके लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से दिल्ली में मुलाकात करके झारखंड के विद्यार्थी शिक्षकों के बकायों का भुगतान करने की मांग की थी. श्री जावड़ेकर ने व्यक्तिगत स्वरूप लेते हुए अपनी उपस्थिति में ही संबंधित अधिकारियों से मीटिंग करायी और यथाशीघ्र राशि जारी करने का निर्देश दिया था. श्रीमती वर्मा ने अब राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह इस राशि का भुगतान दौड़ती से पहले कर

दे. उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के पूरी तरह क्रियान्वयन का मामला काफी दिनों से लंबित रह गया है. आलम यह है कि शिक्षकों को रांची में राजमन्धन के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ा. दरअसल छठे वेतन आयोग के तहत झारखंड के लिए मात्र 34 फीसदी राशि जारी कर दी गयी थी. बाकी राशि को दो किस्तों में भुगतान करना था. पर कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाने के कारण मामला लंबित रह गया. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उन्होंने मंत्री जी के आदेश के बावजूद दिल्ली में ही रहकर इस मामले में फालोअप किया और कागजी कामियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच समन्वय का भी काम किया. उन्होंने कहा कि अंतिम किस्त के भुगतान के लिए भी उनका प्रयास जारी रहेगा.



718 शिक्षकों के ग्रेड वन में प्रोन्नति को हरी झंडी

